



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25092024-257488
CG-MH-E-25092024-257488

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/आश्विन 3, 1946

No. 756]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

बैंक ऑफ़ इंडिया

(मानव संसाधन विभाग)

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 24 सितम्बर, 2024

सं. एचओ: एचआर: टीबीडी:2024-25:01 (ई).— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (2) के खण्ड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के पश्चात और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया (कर्मचारी) पेन्शन विनियमन, 1995 में अतिरिक्त संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- (1) ये विनियम बैंक ऑफ़ इंडिया (कर्मचारी) पेन्शन (संशोधन) विनियमन, 2024 कहलाएंगे।
(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- बैंक ऑफ़ इंडिया (कर्मचारी) पेन्शन विनियमन, 1995 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियम 2 में, खंड (एस) में, उप-खंड (डी) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, यथा :-
"परन्तु यह भी कि 01 नवंबर, 2012 से लागू किया गया विशेष भत्ता हटा दिया जायेगा।
परन्तु यह भी कि कोई कर्मचारी जो 1 नवंबर 2017 को बैंक की सेवाओं में था और जिसकी गतिरोध (स्टैगनेशन) वेतन वृद्धि को उसके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने की तारीख से संशोधित आवधिकता के अनुसार फिर से

समायोजित किया गया है, वह पेंशन के प्रयोजनों के लिए 1 नवंबर 2017 से प्रभावी होकर ऐसी संशोधित गतिरोध (स्टैग्रेशन) वेतन वृद्धि के लिए कल्पित रूप से (नोशनली) पात्र होगा, लेकिन इस तरह के पुनः समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल 1 नवंबर 2020 से प्रभावी होकर या पात्रता की वास्तविक तारीख, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

3. कथित विनियमनों के विनियम 22 में, उप विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, यथा:-
"परन्तु यह तब जबकि किसी कर्मचारी को, जो कामगार (वर्कमैन) के रूप में बैंक की सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक काम पर या वेतनमान वेतन (वेज) पर स्थायी आधार पर अंशकालिक (पार्टटाइम) काम पर नियोजित है, को हटाने से उसकी पूरी पिछली सेवा जव्त नहीं होगी और वह पेंशन लाभ के लिए पात्र होगा"
4. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, यथा:-
"(जी) अंशकालिक से भिन्न किसी कर्मचारी के मामले में, जहां कर्मचारी 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, रुपये तीन हजार नौ सौ पचासी प्रति माह; जहां अंशकालिक (पार्टटाइम) कर्मचारी 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो वहां 1/3 स्केल वेतन पाने वाले अंशकालिक (पार्टटाइम) कर्मचारी के संबंध में रुपये एक हजार तीन सौ पैंतीस प्रति माह, 1/2 स्केल वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में रुपये दो हजार प्रति माह और 3/4 स्केल वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में रुपये तीन हजार प्रति माह।
5. उक्त विनियमनों के विनियम 40 में, -
(ए) उप-विनियम (1) में, -
(i) खंड (बी) में, पहले परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -
"परन्तु यह तब जबकि बेटे/बेटी (विधवा/तलाकशुदा सहित) को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी जब पात्र बेटा/बेटी, सरकारी/निजी क्षेत्र/स्वरोजगार आदि में रोजगार से रुपये बारह हजार प्रति माह से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर दे।";
(ii) खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -
"(सी) माता-पिता के मामले में, पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी यदि सरकारी/निजी क्षेत्र/स्व-रोजगार आदि में रोजगार से माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय रुपये बारह हजार प्रति माह से अधिक हो।";
(बी) उप-विनियम (4) में, -
(i) खंड (ए) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, यथा : -
"(vii) रुपये छब्बीस हजार पांच सौ साठ प्रति माह केवल उन कर्मचारियों, अधिकारी और कामगार दोनों के संबंध में, जो 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या दिवंगत हुए।"
परन्तु यह तब जबकि 1 अप्रैल 2021 को तथा उस दिन से, उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि इन विनियमनों के विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होंगी।
(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, यथा : -
"(vii) रुपये छब्बीस हजार पांच सौ साठ प्रति माह केवल उन कर्मचारियों, अधिकारी और कामगार दोनों के संबंध में, जो 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या दिवंगत हुए।"
परन्तु यह तब जबकि 1 अप्रैल 2021 को और उसके पश्चात्, उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे तथा कर्मचारियों की उपरोक्त उल्लिखित सभी श्रेणी के लिए दोनों पेंशन राशि, कथित विनियमन के विनियम 39 के उप-विनियम (1) या उक्त विनियम के उप-विनियम (3) के खंड (बी) के उपखण्ड (i) और खण्ड (ए)

के उपखण्ड (i) के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, देय होगी।

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाएगा, यथा: -

"(vii) रुपये तेरह हजार दो सौ अस्सी प्रति माह केवल उन कर्मचारियों, अधिकारी और कामगार दोनों के संबंध में, जो 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या दिवंगत हुए।"

परन्तु यह तब जबकि 1 अप्रैल 2021 को और उसके पश्चात्, उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे तथा कर्मचारियों की उपर्युक्त उल्लिखित सभी श्रेणी के लिए दोनों पेंशन की राशि, विनियम 39 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-II में खंड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(4) 01 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2288 अंक से अधिक के प्रत्येक 4 अंक की वृद्धि पर महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक 4 अंक की गिरावट पर वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

परन्तु यह तब जबकि 01 मई 2005 को और उसके बाद से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, महंगाई राहत इस खंड के अनुसार देय होगी:

परन्तु यह तब जबकि 1 नवंबर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2836 अंक से अधिक के प्रत्येक 4 अंक की वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक 4 अंक की गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

परन्तु यह तब जबकि 01 नवंबर 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 4440 अंकों से अधिक के प्रत्येक 4 अंक की वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक 4 अंक की गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

इसके अतिरिक्त दिनांक 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में जैसा भी मामला हो 6352 अंक पर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक 4 अंकों की गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन पर 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।"

7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट III में, खंड (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को डाला जाएगा, यथा:-

"(जी) 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में:

वेतनमान प्रति माह	पारिवारिक पेंशन की मासिक राशि
(1)	(2)
रु. 15,880 तक	‘वेतन’ का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा और ऐसे भत्ते का 30 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान हेतु की जाएगी लेकिन महंगाई भत्ते हेतु नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगा: परन्तु यह तब जबकि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग कम से कम रु. 3,985 प्रतिमाह होगा।
रु. 15,881 से रु. 31,760	‘वेतन’ का 20 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा और ऐसे भत्ते का 20 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान हेतु की जाएगी लेकिन महंगाई भत्ते हेतु नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगा: परन्तु यह तब जबकि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग कम से कम रु. 4,900 प्रतिमाह होगा।
रु. 31,760 से अधिक	‘वेतन’ का 15 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा और ऐसे भत्ते का 15 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान हेतु की जाएगी लेकिन महंगाई भत्ते हेतु नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगा: परन्तु यह तब जबकि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग कम से कम रु. 6,365 और अधिकतम रु. 13,280 प्रतिमाह होगा।

(एच) 1 अप्रैल 2021 के दिन और उसके बाद से खंड (ए) से (जी) प्रभावी नहीं होंगे और उक्त खंडों में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में, “वेतन” का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा और ऐसे भत्ते का 30 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान हेतु की जाएगी लेकिन महंगाई भत्ते हेतु नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगा।”

व्याख्यात्मक ज्ञापन

जिन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे सदस्य बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के उच्च स्तरीय कर्मचारी संघों एवं अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट तथा समझौते की सहमत निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार हैं। अतएव, इस प्रकार के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राजेश सदाशिव इंगले, मुख्य महाप्रबन्धक (मा.स.वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./525/2024-25]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या टीबीडी:पीसी:एचडीपी, दिनांक 29 सितंबर, 1995 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या एचओ:एचआर:टीबीडी:2023-24:319, दिनांक 6 अक्तूबर 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

BANK OF INDIA
(Human Resources Department)
(HEAD OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 24th September, 2024

No. HO:HR:TBD:2024-25:01 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of India, after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely: —
 “Provided also that special allowance introduced with effect from 1st day of November, 2012 shall be excluded:
 Provided also that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later.”
3. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: —
 “Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits”.
4. In regulation 36 of the said regulations, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: —
 “(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017.”
5. In regulation 40 of the said regulations, —
 (a) in sub-regulation (1), —
 (i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted,
 namely: —
 “Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment.”;
 (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
 “(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self-employment, exceeds rupees twelve thousand per month.”;
- (b) in sub-regulation (4),—
 (i) in clause (a), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—
 “(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November, 2017:
 Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.”;

(ii) in clause (b), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017.”;

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub regulation (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of said regulation, as the case may be.”;

(iii) in clause (c), after the sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely: —

“(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.”.

6. In Appendix-II to the said Regulations, for clause (4) the following shall be substituted, namely:-

“(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided that further in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided that also in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension.”.

7. In Appendix III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)
Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.

Above Rs.31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month.
-----------------	--

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent. of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to Provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.”.

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

RAJESH SADASHIV INGLE, Chief General Manager (HR)

[ADVT.-III/4/Exty./525/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* notification number TBD:PC:HDP, dated the 29th September, 1995 and lastly amended *vide* notification number HO:HR:TBD:2023-24:319, dated the 6th October, 2023.